1. डिजिटल संसद और आईसीटी

ई-संसद या डिजिटल संसद को संसदीय संस्थानों के मूल कार्यों और प्रचालनों को सुदृढ़ और मजबूत करने के उद्देश्य से संसदीय संस्थानों में आईसीटी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ई-संसद ई-लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मदद करती है और लोकतांत्रिक तथा सामाजिक-आर्थिक प्लेटफार्मों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। यह संसद के सदस्यों और सामान्य नागरिकों के बीच बातचीत के प्रयासों को मजबूत करने में मदद करती है। इसके अलावा, यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण में भी मदद करती है, सामाजिक समावेश में वृद्धि करती है, सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता लाती है और नागरिकों को अपनी संचालन प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए सरकारी प्रयासों के व्यय को भी कम करती है। सदस्यों के लिए डिजिटल संसद में डिजिटल सदन, सदस्यों का पोर्टल, मोबाइल / टेबलेट ऐप (आईओएस, एन्ड्रॉएड) शामिल हैं। आईसीटी की मुख्य भूमिका सदनों को बेहतर तरीके से मजबूत और परिवर्तित करना है।

2. प्रायोगिक शिक्षा और क्षमता निर्माण

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ई-विधान प्रणाली शुरू करके भारत की पहली उच्च तकनीक वाली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है। ई-विधान प्रणाली की शुरूआत के बाद से सदन से संबंधित सभी दस्तावेज माननीय सदस्यों को उनकी टेबल पर स्थापित टच स्क्रीन और मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। ई-विधान के प्रमुख घटक हैं - कागज रहित विधानसभा सत्र, सदन की समितियों का कागज रहित कार्यचालन और ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन।

ई-विधान को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में पुन: नामित किया गया है और संसदीय कार्य मंत्रालय सभी 31 राज्यों/विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा की तर्ज पर नेवा को आरंभ करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

नेवा की शुरूआत को बढ़ावा देने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया है और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्षमता निर्माण के लिए पूर्ण तकनीकी सहायता के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) का गठन किया है। सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय ने डिजाइन और कार्यक्षमता के संदर्भ में विभिन्न संशोधनों के अधीन रहते हुए नेवा वर्जन 2.0 और नवीनतम अद्यतन मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित की है।

फोटो

[माननीय संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल 24 और 25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसदीय ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए]

राज्य विधानसभाओं / परिषदों के नोडल और अन्य अधिकारियों को नेवा ऐप की विशेषताओं और कार्यों से परिचित कराने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला, 24 और 25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसदीय ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दो दिन की अभिविन्यास कार्यशाला में तकनीकी सत्र और सामूहिक चर्चा की गई थी और प्रतिनिधियों को नेवा के सकारात्मक गुणों से परिचित कराया गया था।

फोटो

[24 और 25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसदीय ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशालय के प्रतिभागियों की सामूहिक फोटो]

इस परियोजना को और मजबूती देने के लिए, विभिन्न राज्य विधानसभाओं में उनके सचिवालय के अधिकारियों, एनआईसी और साथ ही विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को इस एप्लिकेशन का प्रशिक्षण देने और उससे अवगत कराने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की जा रही हैं। अब तक, इस तरह के सफल प्रशिक्षण 14 राज्यों में आयोजित किए गए हैं जैसे कि पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम, बिहार, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोलकाता, असम, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मेघालय।

फोटो

[2 और 3 नवंबर, 2018 को कर्नाटक विधानसभा, बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा और परिषद के लिए आयोजित चरण-I की अभिविन्यास कार्यशाला]

फोटो

[26 और 27 नवंबर, 2018 को अरुणाचल प्रदेश विधान सभा, इटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के लिए आयोजित चरण-I की अभिविन्यास कार्यशाला]

पूर्व क्षमता निर्माण उपायों के क्रम में, सीपीएमयू नेवा, नई दिल्ली में चरण-II की 3 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के नोडल अधिकारियों और

कर्मचारियों की चरण-। का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी टीम को प्रेक्टिकल सत्रों सहित गहन प्रशिक्षण दिया गया।

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सीपीएमयू नेवा टीम के साथ राज्य विधानमंडलों के नोडल अधिकारियों को एप्लिकेशन से संबंधित विभिन्न मामलों का समाधान करने के अलावा उसके मूल प्रचालन से अवगत कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र विभिन्न नोडल अधिकारियों की ओर से विभिन्न विचार और सुझाव आमंत्रित करने में फायदेमंद साबित हुए हैं जो इस परियोजना को आगे ले जाने में एक तरह से प्रेरक कारक रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों, एनआईसी के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए अब तक 1000 से ज्यादा श्रम घंटे के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

ईएफसी ने परियोजना को इस निदेश के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि मंत्रालय सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के साथ सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के विकास और क्षमता निर्माण उपायों पर आगे बढ़े।

इसके अलावा, राज्य सभा के अधिकारियों को अपने सचिवालय में नेवा के वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन को अपनाने की ओर उन्मुख करने के लिए एक परस्पर संवाद सत्र आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ सत्र में भाग लिया और एप्लिकेशन की मुख्य कार्यक्षमता के बारे में सीखने में बहुत अधिक जिज्ञासा दिखाई। राज्य सभा के मौजूदा सिस्टम नेवा प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और राज्य सभा से संबंधित सभी जानकारी अब नेवा एप्लिकेशन पर उपलब्ध है।

इसके बाद, उपराष्ट्रपति सचिवालय में श्री वेंकैया नायडू, भारत के उप-राष्ट्रपति और सभापति, राज्य सभा की अध्यक्षता में, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर एक प्रस्तुति दी गई। सभापति ने नेवा एप्लिकेशन के विकास के माध्यम से विधायिका को डिजिटल बनाने की दिशा में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई पहल और प्रयासों की सराहना की और राज्य सभा में नेवा को अपनाने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, लोक सभा के लिए वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन भी सदस्यों और सचिवालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। पिछले तीन सत्रों के आंकड़ों के साथ सदन को पहले ही अद्यतन किया जा चुका है। हाल ही में, प्लेटफॉर्म को गतिशील और

संवादमूलक बनाने के अलावा उपयोग में आसानी के लिए आंतरिक कार्यक्षमता में मामूली बदलाव भी किए हैं।

3. राज्यों की प्रतिक्रिया

राज्यों ने नेवा पोर्टल को अपनाने में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। राज्यों के एक साथ आने से भारत और मजबूत होगा और यह सहकारी संघवाद का एक जगमगाता उदाहरण होगा। मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए क्षमता निर्माण उपायों से एप्लिकेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों में सफलता मिली है। अब तक राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला, चरण-I में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में प्रशिक्षण कार्यशालाओं, सीपीएमयू में द्वितीय चरण की गहन कार्यशालाओं और अब तक हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों में औसत प्रतिभागिता 5000 से अधिक श्रम दिवसों को पार कर चुकी है। पंजाब, गुजरात, बिहार, मेघालय और कर्नाटक जैसे राज्य मोर्चा संभाल चुके हैं और एप्लिकेशन संबंधी सभी आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं तथा आगामी विधानसभा सत्रों के दौरान नेवा एप्लिकेशन के प्रत्यक्ष परीक्षण के लिए तैयार हैं।

फोटो

[18 से 20 मार्च, 2019 को सीपीएमयू, नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्नाटक विधानसभा के प्रतिभागियों का सामूहिक फोटो]

महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में समृद्ध ऐतिहासिक डेटाबेस मौजूद है और पहले से ही राज्य विधानमंडलों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया गया है जिसे ए.पी.आई. वेब एकीकरण के माध्यम से नेवा से जोड़ा जा सकता है। यह ए.पी.आई. वेब एकीकरण मौजूदा डेटाबेस इंटरफ़ेस से नहीं जुड़ेगा और सदस्यों को एक मंच पर सभी विधानमंडलों के समेकित डेटा तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।

माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री ने भी माननीय वित्त मंत्री से आगामी केंद्रीय बजट में नेवा के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान करने का अनुरोध किया है ताकि नेवा प्लेटफार्म को अपनाने के लिए तैयार राज्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।

4. नेवा की मुख्य विशेषताएं

नेवा एक क्लाउड-आधारित और मोबाइल-अनुकूल तथा सदन स्वचालन के लिए भाषा और मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म के अनुरूप डिजाइन की गई एप्लिकेशन है। एप्लिकेशन को सदस्य केंद्रित और सदन केंद्रित तरीके से डिज़ाइन किया गया है।

नेवा को एक सदस्य-केंद्रित, उपकरण तटस्थ और उपयोगकर्ता के अनुकूल एप्लिकेशन के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि सभी सदस्यों को उनके हस्तधारित उपकरणों/टैबलेट्स में उनके लिए जरूरी समस्त सूचना उपलब्ध कराके सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक संभालने योग्य बनाया जा सके और एक कुशल, समावेशी, शून्य उत्सर्जन-आधारित डेटाबेस का निर्माण करते हुए और ऐसा करके हमारे विधानमंडलों के कामकाज में सुधार करते हुए विधानमंडलों/विभागों की सभी शाखाओं को इसे कुशलतापूर्वक संभालने योग्य बनाया जा सके।

नेवा का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना और ऐसा करके कई एप्लिकेशनों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा भंडार का निर्माण करना है। यह पहल न केवल विधानमंडलों के कामकाज को हमारे नागरिकों के करीब लाकर, नागरिकों को विधेयकों, प्रश्नों-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए कागज-पत्रों तक आसान पहुंच प्रदान करके लोकतंत्र को उनके करीब लाएगी, बल्कि नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक जुड़ाव का अवसर भी प्रदान करेगी और यह सारभूत लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत कदम होगा।

यह एप्लिकेशन सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की सूचना के लिए संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, सभा पटल पर रखे गए कागज-पत्रों के पाठ, समिति के प्रतिवेदन, सदन की कार्यवाही, कार्यवाहियों का सार, मंत्रियों का अनंतिम कलैंडर और रोटेशन, समाचार और प्रेस विज्ञप्ति और संदर्भ सामग्री, समितियों की बैठकों, उनकी कार्यसूची के विवरण सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, वेतन और भत्तों जैसे सदस्यों के व्यक्तिगत दावों के अलावा समय-समय पर नोटिस, समाचार जैसी सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है। एप्लिकेशन पर लाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा, लोक सभा/राज्य सभा टीवी का सीधा प्रसारण भी उपलब्ध है।

सत्र के दौरान, माननीय अध्यक्ष और सदन के सचिव के बीच ई-टिप्पणियां भेजी जा सकती हैं। परिणामों के प्रदर्शन के साथ-साथ टच स्क्रीन का उपयोग करके ई-मतदान भी संभव है। माननीय सांसद/विधायक माननीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठा सकते हैं और दृश्य प्रस्तुतियाँ भी दे सकते हैं। सदन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी संभव है। चर्चा में माननीय सदस्यों का समय डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है और सदन में एल.ई.डी. पर प्रदर्शित किया

जाता है। सदन के पटल पर रखे जा रहे कागज-पत्रों को देखने के मीडियाकर्मियों को लिए टच स्क्रीन भी प्रदान की गई हैं।

नेवा एक डी-सेंट्रलाइज्ड स्टैंडअलोन जेनेरिक डिजिटल एप्लिकेशन है जिसे .NET तकनीक पर एच.पी. पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। इसे स्थानीय डेटा सेंटर में मिररिंग के साथ नेशनल क्लाउड-मेघराज पर होस्ट किया गया है और सभी 40 सदनों के लिए रखरखाव, सुरक्षा और आपदा पुन:प्राप्ति का ध्यान रखा गया है। हाल ही में उड़ीसा में विनाशकारी चक्रवात फानी की घटना, जिसने जान और माल दोनों का भारी नुकसान किया, ने वर्तमान में भुवनेश्वर में तैनात नेवा सर्वरों के लिए उच्च जोखिम उत्पन्न किया था और बिजली की विफलता के कारण 2 दिनों तक एप्लिकेशन बंद रही थी। नेवा डेटा और एप्लिकेशन को दिल्ली स्थित सर्वर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें आपदा पुन:प्राप्ति के साथ-साथ आपातकालीन बैकअप मिररिंग जैसी सुविधाएँ जोड़ी गई हैं, जिससे नेवा एप्लिकेशन विफलता अवरोधी हो गई है। सीपीएमयू नेवा टीम ने सर्वरों को स्थानांतरित करने के लिए दिन-रात काम किया और सिस्टम रिकॉर्ड समय में चालू हो गया था। यह हम सभी के लिए सीखने का एक शानदार अनुभव था।

एम-नेवा मंत्रियों/सदस्यों को प्रश्नों के उत्तरों और सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों सहित सदन के समस्त कार्य की सूचना दैनिक कार्यवाहियां आरंभ होने से 45 मिनट पहले प्राप्त करने में सहायक होगा जबकि माननीय अध्यक्ष सदन के समस्त कार्य की सूचना उपलब्ध होते ही प्राप्त कर सकेंगे। यह उन संपर्कों का भंडार भी होगा जो सभी विधायी सदस्यों, मंत्रालय/विभाग के सचिवों, सचिवालय के अधिकारियों, जिला प्रशासनिक अधिकारियों तथा कई अन्य सहित लगभग 20 हजार संपर्कों की आवश्यकता का ध्यान रखेगा। लगभग 5374 सदस्यों को टेलीफोन और ईमेल के माध्यम से जोड़ने का अनुमान है।

नेवा सदन संचालन संबंधी एप्लिकेशनों के माध्यम से सदन के संचालन में पीठासीन अधिकारियों की भी मदद करेगा। माननीय मंत्री जिन्हें सदन को जवाब देना पड़ता है, वे प्रशासनिक सचिवों से अपने मोबाइल फोन पर अनुपूरक उत्तर की मांग कर सकते हैं। सदस्यों, विधानमंडलों और विभागों के अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए, प्रत्येक स्थान पर नोडल अधिकारी के तहत एक नेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) स्थापित किया जाएगा।

विधानमंडलों में टच स्क्रीन/टैबलेट उपकरणों की स्थापना होगी। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को एक टैबलेट डिवाइस प्रदान किया जाएगा। हाई स्पीड एल.ए.एन./डब्ल्यू.ए.एन. नेटवर्क और सुरक्षित वाई.फ़ाई. नेटवर्क के लिए बैकअप सहित एक मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा स्थापित की

जाएगी। सेवा के इलेक्ट्रॉनिक परिदान के लिए विधानमंडल के सदन (सदनों) में अपेक्षित हार्डवेयर/एक्सेस उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
neva.gov.in
helpdesk-neva@gov.in